भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1050
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के उपाय

1050. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी नौकरियां प्रदान की गईं; और

(घ) इस संबंध में गुजरात का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः 4.2%, 4.1% और 3.2% थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में बेरोजगारी दर में पिछले कुछ वर्षों से गिरावट का प्रवृत्ति है।

इसके अलावा, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर रोजगार का संकेत देने वाला अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः 52.6%, 52.9% और 56.0% था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में रोजगार में बढ़ोतरी का रुझान है। रिपोर्ट राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्तरों के अनुमान प्रदान करती है। जो अनुबंध में संलग्न हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 29.07.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1050 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण (% में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार	कामगार जनसंख्या अनुपात		
		2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	58.6	57.8	58.6
2	अरुणाचल प्रदेश	48.5	47.1	64.9
3	असम	50.5	52.1	54.5
4	बिहार	39.9	39.3	47.0
5	छत्तीसगढ	63.6	64.9	70.1
6	दिल्ली	42.7	42.3	45.8
7	गोवा	43.4	41.6	45.1
8	गुजरात	55.0	56.8	61.5
9	हरियाणा	44.0	42.5	44.9
10	हिमाचल प्रदेश	69.5	71.2	73.8
11	झारखंड	59.6	60.7	60.9
12	कर्नाटक	55.3	53.0	55.6
13	केरल	46.1	48.8	50.5
14	मध्य प्रदेश	60.2	60.7	63.4
15	महाराष्ट्र	53.9	55.9	57.6
16	मणिपुर	41.0	40.6	48.7
17	मेघालय	62.0	60.5	65.8
18	मिजोरम	54.5	48.9	55.2
19	नागालैंड	49.5	58.4	69.4
20	ओडिशा	53.5	52.4	58.9
21	पंजाब	47.2	48.5	50.2
22	राजस्थान	55.3	54.7	58.8
23	सिक्किम	71.3	69.9	74.0
24	तमिलनाडु	56.9	55.8	54.7
25	तेलंगाना	57.8	58.1	57.7
26	त्रिपुरा	53.8	50.6	54.3
27	उत्तराखंड	48.7	48.7	53.5
28	उत्तर प्रदेश	48.0	50.1	53.9
29	पश्चिम बंगाल	53.0	52.7	56.1
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	58.2	59.2	60.0
31	चंडीगढ़	43.1	42.2	45.6
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	54.0	65.8	65.0
33	जम्मू एवं कश्मीर	55.5	58.3	60.7
34	लद्दाख	69.1	58.1	57.0
35	लक्षद्वीप	40.1	37.2	35.5
36	पुडुचेरी	48.1	51.2	49.6
अखिल भारत		**52.6**	**52.9**	**56.0**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई